

राजस्थान सरकार
जिला परिषद, सीकर

क्रमांक: जिपसी/आविप्र/पीए/निर्देश/432-40

दिनांक 09 जुलाई, 2018

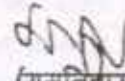
परिपत्र

जिला परिषद व पंचायत समितियों की बैठकों में ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा विद्युत कनेक्शन के लिये आवस्य प्रमाण पत्र तथा नामांतरकरण के लिये वारिस प्रमाण जारी करने की जानेवाली सार्वजनिक कार्यवाही की शिकायतें की जाती रही हैं। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि विद्युत विभाग के द्वारा उपलब्ध कराये गये नियमों के अनुसार कब्जाधारक के शपथ पत्र के आधार पर ही विद्युत कनेक्शन जारी किये जायेंगे तथा इसके लिये भूमि या भवन के स्वामित्व के दस्तावेज नहीं मांगे जायेंगे। राजकीय विचारधक धारागाह, राजमार्गों एवं स्थानीय सड़कों/रास्तों की भूमि पर अपेक्ष कब्जा कर निवास करने वालों तथा व्यवसाय चलाने वालों के शपथ पत्रों के आधार पर जिले में हजारों की संख्या में विद्युत कनेक्शन जारी किये गये हैं। इसके उपरांत जमीन क्षेत्रों में सरपंच से आवसी क्षेत्र में होने का प्रमाण पत्र लाने के लिए आवसी को प्रेरित करना उचित नहीं है।

इसी तरह किसी खातेदार की मृत्यु के उपरांत वारिस प्रमाण पत्र जारी करने के लिये कानूनी क्षेत्र पर सरपंच के अधिकृत नहीं होने के उपरांत राज्य अधिकारियों द्वारा नामांतरकरण दर्ज करने के लिये सरपंच के द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र मांगा जाना विधि तन्मत नहीं है। मृतक खातेदारों के वारिसों की जम्मा करने का दायित्व पटवारी का है। ग्राम पंचायत द्वारा कोरन की बैठक में नामांतरकरण रवीकृत किया जाता है। जिसके लिये किसी वारिस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

इस क्रम में ग्राम पंचायतों की मोटर से पूर्व की तारीखों में फर्जी पट्टे जारी करने तथा ऐसे पट्टे को ब्याधिक कार्यवाही में उपयोग किये जाने, पंजीयन करवाने तथा ग्राम पंचायत की सार्वजनिक भूमि का कब्जा करने के प्रकरण ध्यान में आने के उपरांत स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष में एक बार ग्राम पंचायत के सदस्य, पंचायत प्रसार अधिकारी तथा सचिव द्वारा पट्टों के रिकॉर्ड का पंचायत समिति के पट्टा नियंत्रण ऑफिस से मिलान किया जाकर प्रमाणीकरण किया जायेगा। पंचायत द्वारा पेश पट्टों की सूची जारी की जायेगी तथा सूची से शिवा पट्टे का सरकारी कामकाज में उपयोग लेने पर ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव जम्मित करेंगे कि यह रिकॉर्ड "ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का भाग नहीं है।" ताकि ऐसे पट्टे का पंजीयन नहीं हो सके तथा ब्याधिक कार्यवाही में उपयोग नहीं किया जा सके।

उपरोक्त प्रावधानों को नजर अंदाज करते हुये किसी सरपंच द्वारा कोई प्रमाण पत्र जारी किया जाता है या फर्जी दस्तावेजों को प्रमाणीत किया जाता है तो ऐसा कृत्य पंचायती राज अधिनियम, की धारा 23(1) के तहत अपकीर्तिकर आचरण माना जावेगा।



(समनिवास जाट)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद, सीकर

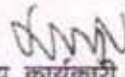
दिनांक 09 जुलाई, 2018

क्रमांक: जिपसी/आविप्र/432-40

सूचनाएं एवं पालनाएं

01 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर

02 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिपराही /घोट /दांतारामगढ /श्रीमाधोपुर /खण्डेला / पाटन / नीमकायाना / क्लेहपुर /लक्ष्मनगढ एक एक प्रति संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी तथा ग्राम पंचायतों के सरपंच/सचिवों को उपलब्ध कराने हेतु।



मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद, सीकर